□□□□ □□□ □□□□

जनसत्ता 12 सतिंबर, 2014: नरेंद्र मोदी की तथाकथति वकिसोन्मुखी सरकार के सौ दनि पूरे होने के साथ ही उनके उस ‘गुजरात मॉडल’ का सच देश के सामने आने लगा है, जसिके दम पर वे सोलहवीं लोकसभा में पूरण बहुमत के साथ आने में सफल हु□ हैं□ लोगों को वह नारा याद होगा, जसिमें नरेंद्र मोदी ने देवालय से पहले शौचालय की बात कही थी□ गौरतलब है कि उनके मुख्यमंत्री रहते हु□ 2003 में गुजरात सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दायर □क हलफनामे में बताया था कि गुजरात पूरी तरह से स्वच्छ राज्य है, जहां □क भी मैला ढोने वाला नहीं है□ लेकनि इसके बावजूद गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से मैला ढोने वाले लोगों के वकिास और पुनर्वास के लि□ करो□ों रुप□ लेना बंद नहीं किया□ कुछ स्वयंसेवी संगठनों और फलि्मकारों ने समय-समय पर इस सच को उजागर किया, लेकनि तब से अब तक राज्य सरकार इसे झुठलाती और ब□-ब□ दावे करती रही□ स्वयंसेवी संगठनों ने उच्चतम न्यायालय के सामने इस सच को रखते हु□ इसकी जांच की मांग उठाई□ फरि न्यायालय के आदेश के मुताबकि इसकी स्वतंत्र संस्था से जांच कराई गई□ जो सच्चाई सामने आई वह न केवल चौंकाने वाली रही, बल्कि ब□ पदों पर बैठे लोगों के दावों की पोल खोलने वाली साबति हुई□ पच्चीस अगस्त 2014 को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने अपने अध्ययन के मुताबकि अकेले गुजरात में मैला ढोने के काम में लगे लोगों की तादाद बारह हजार से भी ज्यादा पाई और यह भी बताया कि इनमें से ज्यादातर वे लोग हैं, जो हाथों से साफ-सफाई का काम करते हैं□

इस रपिोर्ट ने इस तथ्य को सबके सामने रखा कि राजनेताओं के कहने से सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता□ उसके लि□ जमीनी काम करना जरूरी होता है□ रपिोर्ट से इस बात का भी अंदाजा लगता है कि कहीं आने वाले समय में भारत की समस्याओं का ऐसा ही ‘समाधान’ जनता के सामने न रख दयिा जा□, जैसा कि इस मुद्दे पर किया गया□ दूसरी ओर, इस समस्या के समाधान के लि□ काम कर रही □क राष्ट्रीय संस्था ‘गरमिा’ के हवाले से कहा गया कि देश में मैला ढोने वालों की संख्या बारह लाख से भी ज्यादा है□ ऐसे में प्रधानमंत्री देश में वकिास की बैलगा□ी को कैसे बुलेट ट्रेन में बदलेंगे, इस पर संशय है□ इसके अलावा, देश के सौ शहरों को कैसे ‘स्मार्ट सटिी’ में बदला जा□गा, इसका भी भवष्यि अंधयिारे रास्तों से गुजरता हुआ दखिता है□ इसके अलावा, इस रपिोर्ट के सामने आने के बाद उच्चतम न्यायालय गुजरात सरकार से क्या सवाल पूछता है और उसके ग्यारह साल पुराने हलफनामे पर उससे कैसे जवाब मांगता है, उसका इंतजार करना होगा□ लेकनि यहां सवाल यह भी है कि ये झूठ बोले क्यों ग□□ क्या केवल राज्य की शान को और ऊंचाई पर दखिाने के लि□ या □क महत्त्वपूरण समस्या को वकिास के □जेंडे से बाहर रखने के लि□?

फरि उस धन का क्या हुआ जो सालों-साल केंद्र सरकार की ओर से मैला ढोने के काम में लगे लोगों के पुनर्वास और रोजगार के नाम पर राज्य सरकार को मलिता रहा? क्या यह किसी तरह के घोटाले और लापरवाही का □क पन्ना तो नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश का □नआर□च□म घोटाला□ अब यह देखना दलिचस्प होगा कि उच्चतम न्यायालय इस मसले पर क्या रुख अपनाता है□ क्या इस मामले की और गहराई से जांच होगी या फरि मामले को ठंडे बस्ते में डाल दयिा जा□गा?

फेसबुक पेज को लाइक करने के लि□ क्लकि करें- https://www.facebook.com/Jansatta

ट्वटिर पेज पर फॉलो करने केलि क्लकि करें- https://twitter.com/Jansatta